रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261056
CG-DL-E-14022025-261056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2025/माघ 25, 1946
No. 817] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025/MAGHA 25, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फ़रवरी, 2025

का.आ. 821(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन के उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 1 के अधीन आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाए;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3494(अ), तारीख 16 अगस्त, 2024 द्वारा तारीख 16 अगस्त, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोग उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा II के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसकी यह राय है कि सार्वजनिक हित में विस्तार अपेक्षित है, अधिसूचना संख्या का. आ. 3494(अ), तारीख 16 अगस्त, 2024 में निर्दिष्ट अवधि को 16 फ़रवरी, 2025 से छह मास

की और अवधि के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) के उपक्रम में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा. सं. एस-11017/3/2025-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2025

S.O. 821(E).—WHEREAS, the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the industry of Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water, which is covered under item 1 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND, WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 16th August, 2024 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 3494(E), dated the 16th August, 2024;

AND, WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the declaration of public utility service, it may be extended for a period not exceeding six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being of the opinion that in the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O.3494 (E), dated the 16th August, 2024 for a further period of six months from the 16th February, 2025 during which the services engaged in the organisation of Container Corporation of India Ltd. (CONCOR) to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/03/2025- IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.14 22:41:14 +05'30'